and there are subsisting orders for the manufacture of Jaguar aircraft with the Company.

(b) Does not arise.

Steps to uphold secularism in Doordarshan programmes

*176. SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL:

SHRI MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that certain serials/programmes of Doordarshan during the last two-three years have aroused religio-communal passions in the country;

(b) whether it is also a fact that Doordarshan has directly and indirectly been projecting the cause of VHP in respect of Ayodhya temple;

(c) if so, what are the reasons therefor; and

(d) the steps taken/proposed to be taken by Doordarshan to uphold secularism in their programmes/serials and to further the cause of the same in the country?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI GIRIJA VYAS): (a) and (b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) It has always been the endeavour of Doordarshan to telecast programmes to uphold secularism, religious tolerance and communal harmony.

Revival of deep sea fishing industry in Andhra Pradesh

*177. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Government are taking steps to revive the deep sea fishing industry based in Andhra Pradesh; if so, the details thereof;

(b) whether it is a fact that a number of deep sea fishing vessels are being auctioned in Andhra Pradesh;

(c) if so, the details thereof;

(d) whether these vessels are being auctioned at very low prices; and

(e) what measures are being taken to give suitable price for fish catches in Andhra Pradesh?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) Yes, Sir. A scheme for rehabilitation of deep sea fishing industry has been formulated by the Shipping Credit and Investment Company of India Ltd., Bombay which is also applicable to the deep sea fishing industry based in Andhra Pradesh also.

(b) The Shipping Credit & Investment Company of India Ltd. (SCICI) organised auction of deep sea vessels in January and May, 1991. However, no vessels was auctioned due to low value fetched at the auction as well as non-compliance of terms and conditions of the auction by the participants.

(c) Does not arise.

(d) Does not arise.

(f) Most of the deep sea fishing vessels operating in the Andhra Pradesh Coast are in the private sector. The Government of India do not fix the support price for fish.

केन्द्रीय निर्माण केन्द्र

*178. **श्री कपिल वर्मा :**

श्रीमती वीणा वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अत्यधिक लागत से खेलगांव में स्थापित किये गये दूरदर्शन के केन्द्रीय निर्माण केन्द्र

की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है; यदि हां, तो इस केन्द्र पर कितनी राशि खर्च की गई थी और इसकी क्षमता का कितना उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) क्या यह भी सही है कि रामचरितमानस की रिकार्डिंग बाहर से कराई गई थी; यदि हां तो इसके लिए कितनी राशि का भुगतान किया गया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) (क) जी, नहीं । दरदर्शन के केन्द्रीय निर्माण केन्द्र के लिए वार्षिक निर्माण के जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उनके संदर्भ में उसकी क्षमता का उपयोग प्राय: संतोषजनक रहा है । इस केन्द्र की स्थापना पर 44.73 करोड रुपए की लागत आई है ।

(ख) जी, हां । तथापि, यह प्रस्तुति आकाशवाणी की है । इस कार्यक्रम पर 65 लाख रुपए की अनुमानित कुल लागत में से बाहर के स्टुडियो में रिकार्डिंग के लिए अब तक 6,44,600/- रुपए की राशि का भुगतान किया गया है ।

मध्य प्रदेश के लिए स्वीकृत विकास योजनाएं

*179. **श्री अजीत जोगी :**
श्री राधाकिशन मालवीय :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मध्य प्रदेश में कार्यान्वयन हेतु किन-किन विकास योजनाओं को योजना आयोग ने स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना आयोग के पास अन्य कौन-कौन सी योजनाएं स्वीकृति हेतु लंबित हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा स्कीमवार स्वीकृति नहीं दी जाती है । राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं के लिए केवल शीर्ष/उपशीर्ष वार परिव्ययों का अनुमोदन किया जाता है । स्कीमवार आवंटन राज्य सरकारों द्वारा (मध्य प्रदेश सहित) स्वयं किया जाता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

*180. **श्री शंकर दयाल सिंह :**
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान राची स्थित हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन ने कितना व्यापार किया :

(ख) क्या यह सच है कि इस कारपोरेशन के पास इसकी क्षमता की तुलना में कम आर्डर है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा किया गया कुल कारोबार अर्थात् कुल बिक्री निम्न प्रकार है :–

1988–89	262.51 करोड़ रुपये
1989–90	259.97 करोड़ रुपये
1990-91	183.32 करोड़ रुपय

(ख) जी, हां ।

(ग) इस समय सरकार के हस्तक्षेप के कारण, प्रयोक्ता क्षेत्रों ने हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को आर्डर देने शुरू कर दिए हैं और 1–7–1991 को कम्पनी की क्रयादेश स्थिति 710 करोड रुपये है जो कम्पनी के इतिहास में सर्वोत्तम है ।